

संपादकीय

प्रणव मुखर्जी की किताब से बवाल

पूर्व राष्ट्रपति स्व. प्रणव मुखर्जी की किताब द रेंसिडेंसियर इयर्स को लेकर कांग्रेस में बवाल मच गया है। प्रणव मुखर्जी की इस किताब का जनवरी 2021 में विमोचन होने जा रहा है। पांच दशकों तक भारतीय राजनीति से जुड़े रहे प्रणव मुखर्जी की इस किताब में कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की गई है। प्रणव मुखर्जी ने लिखा है कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस नेतृत्व में राजनीतिक फोकस खो दिया। सोनिया गांधी जहां पार्टी मामलों को देखने में विफल हो गई वहीं सदन में लंबे समय तक अनुपस्थित रहने से ताल्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने अन्य सांसदों से व्यक्तिगत संपर्क खो दिया। उन्होंने लिखा है कि देश में शासन करने का नैतिक अधिकार प्रधानमंत्री के पास निहित होता है लेकिन मनमोहन सिंह गठबंधन को बचाने में व्यस्त रहे, जिसका शासन पर असर पड़ा। प्रणव मुखर्जी की इस किताब पर फिलहाल कांग्रेस नेताओं ने कोई टिप्पणी नहीं की है। पूर्व केन्द्रिय मंत्री विरप्पा मोहिली ने कहा है कि अभी किताब का विमोचन नहीं हुआ है और यह समझना होगा कि मुखर्जी ने किसी परितेक्ष में यह बातें लिखी है। पूर्व केन्द्रिय मंत्री सलमान खुशिंद ने भी कहा है कि वे पहले किताब को पूरी तरह पढ़ लेने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। प्रणव मुखर्जी जैसे इतने व्यापक अनुभव वाले शख्स ने अगर कुछ लिखा है तो उस किताब को पूरा पढ़ने की जरूरत है तभी पता चलेगा कि उन्होंने किस परितेक्ष में ऐसा लिखा है। गौरतलब है कि 2004 में जब कांग्रेस ने नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी थी तब प्रधानमंत्री पद के लिए प्रणव मुखर्जी का नाम उभरा था लेकिन मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया और प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति बनाए गए थे। बहरहाल प्रणव मुखर्जी की यह किताब जब प्रकाशित हो जाएगी तो उससे लेकर कांग्रेस में और बवाल मचने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी इस समय संक्रमण काल से गुजर रही है। एक के बाद एक उसे पराजय का सामना करना पड़ा रहा है। कई राज्यों में तो कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसे क्षेत्रिय दलों का पिछलग्गू बनना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने अब कांग्रेस से किनारा ही कर लिया है। बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को आखें दिखाने लगा है। बंगाल में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में वामपंथी पार्टियां कांग्रेस से गठबंधन करने की मानसिकता में नहीं दिख रही है। कांग्रेस के भीतर अंतर कलह इस कदर तेज हो गई कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तुलसीमानवी आजाद को बगावती सुर अख्तियार करने पड़े है। कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेता पार्टी आलाकमान के फैसलों से नाखुश बताए जाते है। ऐसी स्थिति में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस लगातार अपना जनाधार खो रही है। कांग्रेस नेतृत्व को मंथन करने की आवश्यकता है ताकि कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा किया जा सके और वह कम से कम सशक्त विपक्ष की भूमिका तो निभा सके।

विचार

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे: सुविधाओं तक पहुंच

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) के ताजा आंकड़े कई दृष्टियों से ध्यान देने लायक हैं। 2015-16 में जारी हुए चौथे सर्वे के बाद आए इस पांचवें सर्वे के नतीजे हालांकि पूरे देश के नहीं, सिर्फ 17 राज्यों और पांच केंद्र शासित इकाइयों के ही हैं। कोविड-19 के कारण अभी यह अधूरा है। लेकिन फिर भी इन आंकड़ों से चार साल की इस अवधि में जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आए सुधार के ठोस संकेत मिलते हैं। बाकी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वे से जुड़ा फील्ड वर्क अब दोबारा शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगले छह महीनों में एनएफएचएस की संपूर्ण रिपोर्ट जारी हो जाएगी। लेकिन पहले चरण की इस रिपोर्ट में कोरोना महामारी शुरू होने के ठीक पहले तक की स्थिति दर्ज हुई है और यह इस अर्थ में मौजूदा मोदी सरकार के प्रशासनिक कामकाज का आईना बन सकती है कि इसके पहले कार्यकाल की शुरुआत के कुछ बाद से लेकर आखिर तक की अवधि इसमें कवर हो जाती है। चौथे सर्वे के मुकाबले इस पांचवें सर्वे में बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच में काफी सुधार दिखता है। उदाहरण के लिए आबादी में बिजली की सुविधा हासिल कर चुके परिवारों का अनुपात ज्यादातर राज्यों में बढ़ा है। इसके अलावा शुद्ध पानी के स्रोतों तक पहुंच वाले परिवारों की संख्या भी ज्यादातर राज्यों में बढ़ी है। यही नहीं, शौचालय की सुविधा और स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता के मामले में भी तकरीबन सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में हालात बेहतर हुए हैं। हालांकि इस बेहतरी को दर्ज करते हुए भी ये आंकड़े बताते हैं कि इन मोचों पर अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जबर्दस्त कामयाबी के बावजूद तकरीबन एक चौथाई आबादी आज भी धुआं न छोड़ने वाले ईंधन से वंचित है। ऐसे ही स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि संपूर्ण आबादी को शौचालय उपलब्ध हो गया है, लेकिन ताजा सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक करीब एक चौथाई आबादी ऐसे घरों में रहती है जिनमें शौचालय नहीं है। ऐसे परिवारों को सामूहिक शौचालय का सहारा लेना पड़ता है। बहरहाल, इनसे अलग एक मोर्चा ऐसा है जहां हालात सुधरने के बजाय पहले से और बदतर हुए हैं। वह है बच्चों में बढ़ता कुपोषण। 2015-16 के सर्वे में इस मोर्चे पर सुधार दर्ज किया गया था। यानी कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई थी। मगर एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट के मुताबिक उस के हिसाब से कम लंबाई वाले बच्चों की संख्या 13 राज्यों में और लंबाई के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों की संख्या 12 राज्यों में बढ़ी है।

पाठकों की बात

संग्राम जीवन का

संग्राम जीवन का नही थमता , न थमता सिलसिला जीत और हार का कभी खुशी के पल तो आते हैं कभी मायूसी के दिन पर न रुकता प्रत्सप्त मन की मार का सोते हुए कभी दिखें स्वप्न दुरुह से कभी सब बिछड़ा लगे रहे से पर नही टिकता ज्ञान नशा अहंकार का लोग मरते हैं फिर जन्मते हैं यही तो ध्येय है संसार का।

– **मधुलिका शुक्ला**

धरे हाथ पर हाथ

धरे हाथ पर हाथ सब, ताक रहे मुख आज। सड़ी मछलियां ताल में बिगड़ा हुआ समाज। बिगड़ा हुआ समाज, दोष किसके सिर मढ़ते। दे दी जिनको छूट, वही कौतुक नित करते। हड़ व्यवस्था भंग, कौन अब हाफ करे सब। पुलिस न्याय नेतृत्व, हाथ पर हाथ धरे अब।

– **हरिवल्लभ शर्मा ‘हरि’**

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

ख़ास प़ाती | अशकों की रवानी में उल्फत का

अशकों की रवानी में उल्फत का फ़साना है कब झाँक सका दिल में बेदर्द ज़माना है दुनिया की रखावत से नाकाम हुए आशिक किस्मत की लक़रीं तो इक कोरा बहाना है शम्मा की आशिकी में परवाना जला शबभर दस्तूर मुहब्बत का हर हाल निभाना है धरती को मयस्सर है अम्बर की इनायत कब ख्वाबों में अधूरी हर ख्वाहिश का ठिकाना है बेचैन सवेरों सँग आँखों में कटी रातें आ बैठे तुन्हें अपना दिल हाले सुनाना है।

– **पूजा बंसल**

हर नारी मे निहित एक नदी

हर नारी मे निहित एक नदी है,जो.जानती है नियति मेरा सागर है। वह यह.भी जानती है कि, होकर विलीन सागर के बाहु पास में, अपना अस्तित्व विलुप्त हो जाएगा। फिर भी प्रेम की पराकाष्ठा है कि मीलों.की सम विषम यात्रा कर, बड़े अरमानों से कल कल बहती, निश्छल निर्मल सागर मे मिलकर नदी निर्मूल निराकार हो जाती है।

– **कुमुद रंजन झा**

तन्हा सफ़र लम्बी जुदाई. आंखों

तन्हा सफ़र लम्बी जुदाई.. आंखों में नमी सदा मुक़ुद्दाई.. दिल की बेचैनी नज़र नहीं आई,.. बेपरवाह रहा वो वफ़ा भी रंग लाई.. इश्शश इश्शश.. इश्क़ ने दी दुहाई.. साँसों ने धड़कन.. प्रीत ने रीत निभाई.. फिर वफ़ा भी चुप हवो से निकली बेवफ़ाई.. हौले से वक़्त गुज़रा.. चुपके से रो पड़ी तन्हाई.. कि नंदिता अब तो समझो सही न जाएगी ये जुदाई......!!

– **नंदिता तनूजा**



डॉ नीलम महेंद्र

आंदोलन स्थल पर

रोटी बनाने की मशीनें, हाइड्रे पर

जगह जगह लगी वाशिग मशीनें,

ट्यूब वाटर प्रत्य का संचालन करने

वाली मोबाइल सोलर बैन को

मोबाइल प्लेन चार्ज करने और

बैटरी बैक के रूप में तब्दील

करना, बिजली के लिए सोलर

पैनल और इन्वर्टर का प्रयोग।

अगर हमारे किसानों ने एक हाइड्रे

की सड़क पर अपने दम पर यह

इंफ़स्ट्रक्चर खड़ा किया है तो इसका

मतलब यह है कि हमारे किसान

हर प्रकार से सक्षम है और

आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी

बख़ूबी जानते है तो फिर वे अपने

इस हुनर के लिए सोलर

पैनल और इन्वर्टर का प्रयोग।

करने की बजाए खेती और फ़सल

को उन्नत करने में लगते तो वो

ख़ुद भी आगे जाते और देश की

तरक्की में भी अपना महत्वपूर्ण

योगदान देते। लेकिन हमारे देश के

किसानों की हकीकत किसी से छुपी

नहीं है।देश के 86 प्रतिशत किसान

छोटे किसान है वो ख़ुद खेती में

निवेश भी नहीं कर सकते।

किसानों द्वारा की जाने वाली

आत्महत्या के आकड़े उनकी

दयनीय स्थिति बताने के लिए काफी

है। इसलिए जब इस किसान

आंदोलन के ज़रिए हमारे देश के

किसानों की यह विशेषग़ासी

तस्वीरें ख़ाकने आती है तो इनको

राजनीति की बू आती है।



राजेश माहेश्वरी

वास्तव में अब

लोकतंत्र में विचार कम, पत्थर

अधिक चलने लगे हैं।हिंसा की

इस बढ़ती जा रही घिताजनक

प्रवृति के पीछे राजनीति का

अपराधीकरण भी एक बहुत

कारण है। जब अपराधिक

एक्टनूक्ति के लोग यानि कानून

को अपने जुते की नौक पर

रखने वाले लोग चुनाव में

जीतकर विधानसभाओं और

संसद में आएंगे, तो वे वहां भी

कैसा ही आवरण करेंगे जिसके वे

आदी हैं। और यह आवरण

लोकतंत्र की भावना के अनुरूप

तो नहीं हो सकेता। ताजा

घटना में भाजपा और तृणमूल

कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप

प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन

ऐसी हिंसा कोई करे,

लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ

और लोकतंत्र को कमजोर

करती है। किसी भी तर्क और

बहाने इसका समर्थन करना

निंदनीय और शर्मनाक है।

समस्या का समाधान हां या ना में नहीं संवाद में

देश में लगभग एक पखवाड़े से जारी किसान आंदोलन भारत के सशक्त लोकतंत्र का बेहतरीन और विपक्ष की ओछी राजनीति का ताजा उदाहरण है। क्योंकि आंदोलन के पहले दिन से ही किसानों की मांगों का जिस प्रकार केंद्र में बहुमत वाली सरकार सम्मान कर रही है, उनकी आशंकाओं का समाधान करने का हर सम्भव प्रयास कर रही है वो सराहनीय है। यह बात सही है कि मौजूदा सरकार कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष के पिछले चार पांच सालों के इतिहास को देखते हुए इन कृषि सुधार कानूनों को लाने से पहले ही किसान नेताओं या फिर राज्य सरकारों को विश्वास में ले लेती तो आज पूरा देश इस अराजक स्थिति और अनावश्यक विरोध की राजनीति से बच जाता लेकिन या तो सरकार ने इस मामले में दूर की दृष्टि नहीं रखी या फिर उसने विपक्ष की ताकत को कम आंक लिया। खैर अब वो इस स्थिति में अपना नरम और सकारात्मक रुख का परिचय दे रही है चाहे वो किसानों द्वारा दिल्ली के बुराड़ी मैदान में आंदोलन करने से मना कर देना हो या किसानों द्वारा सरकार से बिना शर्त बात करने की मांग करना हो। चाहे कृषि मंत्री से लेकर गृहमंत्री तक विभिन्न स्तरों पर किसान नेताओं की बैठकों का दौर हो।और या फिर अपने ताजा कदम में आखिर किसानों की मांगों को देखते हुए सरकार द्वारा कृषि कानूनों में संशोधक शाेषण होता है। वो मंडियों में कम दामों पर अपनी उपज बेचने के लिए आढृतियों के आगे विवश होते हैं और ये आढृतियें इन्हीं फ़सलों को आगे बढ़ी हुई मंशा स्पष्ट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ़ किसान संगठनों का रवैया किसान नेताओं की मंशा और विश्वसनीयता दोनों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। क्योंकि इन कानूनों के जिन मुद्दों को उत्क़रक यह किसान आंदोलन खड़ा किया गया है सरकार उन सभी पर संशोधन करने के लिए तैयार है। बावजूद इसके किसान नेता संशोधनों को मानने के बजाए कानून वापस लेने की

अपनी मांग पर ही अड़े हैं। तो किसान आंदोलन पर सवाल यहीं से खड़े हो जाते हैं क्योंकि, 2015 की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देश के केवल 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है लेकिन फिर भी किसान एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था पर आश्वासन चाहते हैं जो कि



सरकार लिख कर देने को तैयार है। किसानों को डर है कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी जबकि यह कटु सत्य है कि मौजूदा मंडी व्यवस्था के अंतर्गत मंडियों में ही किसानों का सर्वाधिक शाेषण होता है। वो मंडियों में कम दामों पर अपनी उपज बेचने के लिए आढृतियों के आगे विवश होते हैं और ये आढृतियें इन्हीं फ़सलों को आगे बढ़ी हुई मंशा स्पष्ट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ़ किसान संगठनों का रवैया किसान नेताओं की मंशा और विश्वसनीयता दोनों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। क्योंकि इन मंडियों के जिन मुद्दों को उत्क़रक यह किसान आंदोलन खड़ा किया गया है सरकार उन सभी पर संशोधन करने के लिए तैयार है। जिस को विकल्प देने को भी तैयार है। जिस कॉन्ट्रैक्ट फ़ॉर्मिंग कानून को लेकर भ्रम

फैलाया जा रहा था कि किसानों की जमीनें प्राइवेट कंपनियों द्वारा हड़प ली जाएंगी उसको लेकर भी कानून में स्पष्टता की जाएगी कि खेती की जमीन या बिल्डिंग गिरवी नहीं रख सकते। किसानों ने यह मुद्दा उठाया था कि नए कृषि कानूनों में कृषि अनुबंधों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है तो सरकार ने

फैलाया जा रहा था कि किसानों की जमीनें प्राइवेट कंपनियों द्वारा हड़प ली जाएंगी उसको लेकर भी कानून में स्पष्टता की जाएगी कि खेती की जमीन या बिल्डिंग गिरवी नहीं रख सकते। किसानों ने यह मुद्दा उठाया था कि नए कृषि कानूनों में कृषि अनुबंधों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है तो सरकार ने

संशोधन में आश्वासन दिया है कि कंपनी और किसान के बीच कॉन्ट्रैक्ट की 30 दिन के भीतर रजिस्ट्री होगी। किसान बिजली से जुड़े नए कानून लागू करने के खिलाफ़थे, सरकार ने संशोधन में आश्चस्त किया है कि बिजली की पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी और वो बिजली संशोधन बिल 2020 नहीं लागूगी। किसानों को आपत्ति थी कि नए कानूनों से वो निजी मंडियों के चुंगल में फंस जाएंगे सरकार ने संशोधित प्रस्ताव में निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है ताकि राज्य सरकारें किसानों के हित में फैसले ले सकें। लेकिन किसान नेताओं द्वारा सरकार के इस संशोधित प्रस्ताव को तुकराना और संशोधन नहीं केवल कानून वापस लेने की मांग पर अड़ जाना, सरकार के साथ बैठकों में कानून पर बात करने के बजाए (नयस और

नो+) हों या ना+ के प्लेकार्ड लहराना या फिर सरकार द्वारा संशोधन भेजने के बावजूद आंदोलन और तेज करने की घोषणा करना, जिसमें अडानी अंबानी के सामन का बहिष्कार करना, जैसे कदम उठाए जा रहे हैं , इस आंदोलन में किसानों के पीछे छुपे असली चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब सरकार के साथ 9 तारीख को बैठक प्रस्तावित थी तब किसान संगठनों द्वारा 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान,इस बंद को समूचे विपक्षी दलों का समर्थन और राहुल गांधी शरद पवार समेत विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल का राष्ट्रपति से मिलकर इन कानूनों को रद्द करने की मांग करने, ये सभी बातें अपने आप में इसके पीछे की राजनीति को उजागर कर रही हैं। साथ बात यह है कि इस आंदोलन में रहने खाने से जुड़े मूलभूत विषय हो या सरकार से बात करने की रणनीति तैयार करने जैसे गंभीर विषय हों जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं या फिर प्रसाद के रूप में काजू किशमिश बांटने जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं वो इस आंदोलन को शाहीन बाग़ जैसे आंदोलन के समकक्ष खड़ा कर रहे हैं। जब केजरीवाल एक तरफ़ दिल्ली में इन कृषि कानूनों में से एक को लागू करते हैं और दूसरी तरफ़ किसानों के बीच जा कर इन कानूनों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। या जब राहुल गांधी किसानों से कानून वापस लेने तक पीछे नहीं हटने का आह्वान करते हैं लेकिन अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन्हीं कृषि सुधारों को लागू करने का वादा करते हैं। या जस शरद पवार आज इन कानूनों के खिलाफ़ किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं लेकिन खुद कृषि मंत्री रहते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर इन कृषि सुधारों को लागू करने की वकालत करते हैं। लेकिन राजनीति से इतर यह बात भी सही है कि सरकार द्वारा लाए इन कृषि सुधार कानूनों में छोटे किसानों के मद्देनजर और सुधार की गुंजाइश हो सकती है।

और किसान संगठनों का मुख्य उद्देश्य इन छोटे किसानों के ही हित की रक्षा करना

राजनीतिक असहिष्णुता से कमजोर होता लोकतंत्र

दूसरों के विचारों और अधिकारों का सम्मान करना और अपनी बात किसी पर जबर्दस्ती न थोपना लोकतंत्र के बुनियादी मूल्य हैं। लेकिन पिछले सात दशकों में भारत में असहिष्णुता की प्रवृत्ति काफी बढ़ी है। यूं तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का अतीत पुराना रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति को भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता। इसी श्रृंखला में बीते दिनों विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जगत्प्रकाश नड्डा के काफ़िले पर हमला किया गया है। नड्डा पश्चिम बंगाल के प्रवास पर थे और चुनावों के मद्देनजर तैयारियों और माहौल का जायजा लेने में व्यस्त थे। उनका काफ़िला कोलकाता से डायमंड हार्बर जा रहा था, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे का संसदीय क्षेत्र है। बुलेटफ़फ़ वाहन होने के कारण वह बच गए, लेकिन पार्टी महासचिव एवं बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयगींय और पार्टी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय आदि को चोटें आई हैं। दरअसल, बंगाल में भाजपा के लगातार बढ़ते जनाधार से बौखलाकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ़ से तल्व प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक नेता होगा, जो यह बात नहीं कहता कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। शायद ही कोई हिंसा की आलोचना में पीछे रहता है। पर सच यही है कि भारतीय राजनीति में हिंसा कोई नयी बात नहीं है। निस्संदेह, बंगाल तो भद्रजनों की भूमि है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष यह है कि बंगाल में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, समर्थकों के बीच हिंसक टकराव का पुराना इतिहास रहा है। 1970 के दशक से यह हिंसा जारी है। तब के मुख्यमंत्री सिन्धुधर शंकर रे ने ऐसी ही हिंसा को हवा दी थी। फिर 34 लंबे सालों तक वाममोर्चा ने बंगाल में शासन किया। ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य सरीखे महान मुख्यमंत्री हुए, लेकिन बंगाल के चप्पे-चप्पे, इलाके-दर-

इलाके हिंसा की 'लाल फ़ैज' स्थापित की जाती रही। वे गुंडे और हिंसक तत्त्व लाल पार्टी के लिए चुनावी बु्थ भी छपती थी और अवैध मतदान भी कराया जाता था। 2011 में ममता



सत्ता में आई, तो वह फ़ैज भी स्थानांतरित हो गई। अब 2014 में मोदी उभार के बाद वही जमात ममता बनर्जी और भाजपा में विभाजित है और अपने-अपने नेतृत्व के इशारे पर ईंट, पत्थर, कांच की बातलें, गोली और बम की भाषा में बातली है। कोई एक ही पक्ष हिंसा नहीं कर रहा है। कई इलाके नक्सली हिंसा की जद में रहे हैं।

कालांतर वामदल के कैडर में ऐसे घटक शामिल रहे जो बाहुबल के आधार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करते रहे। जब तृणमूल कांग्रेस ने 'लाल दुर्ग' पर पार्टी का परचम लहराना शुरू किया तो पार्टी को भी हिंसक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि कालांतर वे ही तत्व तृणमूल कांग्रेस के कैडर में शिफ़्ट हो गये, जिसके चलते स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की परंपरा बाधित हुई। अब बदलाव की आहत में भाजपा को उसी तरह के हिंसक प्रतिरोध का सामना सत्तारूढ़ दल के कैडर से करना पड़ रहा है, जैसे वाम सत्ता के पराभव के दौरान तृणमूल कांग्रेस को करना पड़ा था।

यानी राज्य में राजनीति का चेहरा ही बदलता है, मोहरे अदला-बदली करते रहते हैं। आंकड़ों की जुबानी बात की जाए तो बीते चार सालों में भाजपा के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, तो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक भी मारे गए हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफ़िले पर पथराव करना, हमले की योजना तैयार कर घेराबंदी करना, वाहनों के काफ़िले के सामने लेट कर और काले झंडे दिखा कर अवरोध पैदा करना कमोबेश बंगाल की बुनियादी संस्कृति नहीं है। बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, राजा राममोहन राय, रवींद्र नाथ टैगोर, बंकिमचंद्र चटर्जी और ईश्वर चंद विद्यासागर सरीखे महान और कालजयी व्यक्तित्वों की धरती है। निस्संदेह, पश्चिम बंगाल में लगातार जारी हिंसा और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं का सिलसिला लोकतंत्र की शुचिता के लिये बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर देश के सभी राजनीतिक दलों को गंभीर मंथन करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस हमले को बेहद गंभीरता से लिया है। बंगाल सरकार के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से स्पष्टीकरण मांगने के साथ-साथ राज्यपाल की रपट भी मांगवाई गई है। इसी दौरान खबर आई है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र को रपट मेल कर दी है। फ़ैकस यह रहा है कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल है। ऐसे में देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करती है अथवा नहीं? बंगाल में विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई, 2021 में होने हैं। अभी तक सदन में भाजपा के मात्र 3 विधायक हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीत कर सभी को चैंक दिया था। करीब 125 विधानसभा सीटों पर जीत! यकीनन ममता सरकार के लिए यह गंभीर चुनौती है।

QUIZ TIME

1) राज्य शासन द्वारा ‘गढ़िया महोत्सव’ किस जिले में मनाया जाता है?

2) ज्पारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है?

3) ‘मरकुद्वीप’ छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्द है?

4) ‘छत्तीसगढ़ी लोक बैले’ कहा जाता है:

5) यह बांस का बना बांसुरी जैसा सुषिर वाद्य का नाम

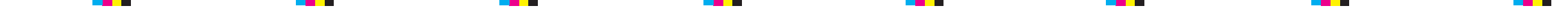
बताइए?

1)छत्तीसगढ़ (५) 2)बलसोर (४) 3)मरकटपुर (३) 4)दुर्ग (७) 5)मृदंग (1) -बालासोर

आज का इतिहास

नई दिल्ली । 1631 - इटली के माउंट विसुवियस में ज्वालामुखी विस्फोट से छह गांव तबाह, चार हजार से अधिक लोग मारे गये। 1707 -जापान के माउंट फुजी पर्वत में अंतिम बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। 1862-नेपाल में संविधान लागू हुआ। 1889 - ब्रिटिश संसद की अधिकार घोषणा को राजा विलियम और रानी मेरी ने स्वीकृत कर शासन में जनता के अधिकार को मान्यता दी। 1920- चीन के कांसू प्रांत आए भूकंप के कारण से एक लाख से अधिक लोगों की मौत। 1927- आस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने न्यूसाउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच से अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत की। 1920 - कलकत्ता (अब कोलकाता) विद्युत आपूर्ति निगम ने हुगली नदी में नहर की खुदाई आरंभ

की। 1937 - भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक़ेबाजों में से एक हवा सिंह का जन्म। 1951 -हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की स्थापना की गयी। 1958- कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में एक गोदाम में लगी भीषण आग में 82 लोगों की मौत। 1959- पश्चिमी पाकिस्तान के लोवाराय दर्रे में भारी हिमपात से 48 लोगों की मौत। 1971 - भारत और पाकिस्तान के बीच संपर्क विराम पर सहमति के बाद बंगलादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1985 -तमिलनाडु के कलपक्कम में पहले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफ़्फ़ीटीआर) की स्थापना की गयी। 1991 - कजाखस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की। 1993- नयी दिल्ली में ‘सभी के लिए शिक्षा’ सम्मेलन प्रारम्भ।



सेवा केन्द्र में भी बनवा सकते है आयुष्मान कार्ड

सिवनी । आम नागरिक लोक सेवा केन्द्र में भी आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनवा सकते है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 लाख रुपये तक नि:शुल्क लाभ दिया जाता है। सभी सबल कार्ड धारी, खाद्यान पूर्वी धारी एवं ऐसे सभी लोग निनका नाम एस.ई.सी. सूची में है। वे सभी आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र है। आप अपना आयुष्मान कार्ड अपने पास के लोक सेवा केन्द्र में जाकर बनवा सकते है। वे अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों का कार्ड बनवाए। उक्त आयुष्मान कार्ड की सेवा प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क 30 रुपये नियत है।

उद्यान विभाग में रिसोर्स पर्सन आवेदन आमंत्रित

सिवनी । सहायक संचालक उद्यान विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री सुष्म, खाद्य उन्नयन योजना (पीएम एफएमई स्कीम) अंतर्गत योजना के दिशा-निर्देशानुसार जिलास्तरीय क्रियाव्ययन समिति का गठन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के दिशा-निर्देश की कड़िका अनुसार जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर लाभार्थियों को हेण्ड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिये रिसोर्स पर्सन (फेसिलिटेटर के रूप में) चयन किया जाना है ।

हाई स्कूल के सामने नाली के खुले चेंबर से बढ रही हैं दुर्घटनाएं



■ साहीबौका। (नव प्रदेश) शासकीय बालक हाई स्कूल के सामने नव निर्माण नाली का चेंबर खुला हुआ है जिससे आए दिन आने जाने वाले एवं स्कूल में प्रवेश करने वाले दोपहिया वाहन खुले चेंबर में धंस जाते हैं स्कूल संचालित हो रहे हैं इस वजह से छात्र-छात्राओं का स्कूल में प्रवेश प्रारंभ है हाई स्कूल के गेट के

सामने ही चेंबर खुला हुआ है नगर परिषद के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते स्कूल प्रबंधन द्वारा कई बार चेंबर में जाली लगाने के लिए नगर परिषद में कहा गया लेकिन अभी तक चेंबर को खुला ही रखा गया है डू-24 चेंबर बनाया गया है जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं वही लोगों का यह भी कहना है कि उस वक्त

चेंबर का कोई औचित्य नहीं है इसके बाद भी नाली निर्माण के दौरान जबरिया चेंबर बना दिया गया अब परेशानी का सबब बना हुआ है लोगों ने जल्द ही चेंबर पर जाली लगाने की मांग नगर परिषद के समक्ष सक्षम अधिकारियों से की है

नशा मुक्ति कार्यक्रम

उप थाना प्रभारी ने नशा के दुष्परिणामों से लोगों को किया जागरूक

■ साहीबौका। (नव प्रदेश) पुलिस अधीक्षक द्वारा संपूर्ण जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत स्थानीय उप थाना प्रभारी द्वारा ग्राम सहावन में भी नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया ग्राम पंचायत



कार्यालय सहावन में उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रभारी पीयूष साहू द्वारा लोगों को नशा छोड़ने के लिए कहा गया एवं नशा से होने वाले दुष्परिणामों को भी बताया उक्त कार्यक्रम में ग्रामीण जन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया दरबई लघु जलाशय का वर्चुअल लोकार्पण

■ सिवनी। (नव प्रदेश) मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सोमवार 14 दिसंबर को वर्चुअल माध्यम से जिले के छपारा विकासखंड अंतर्गत आने वाले दरबई लघु जलाशय का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को खुशियों की सौगात दी। 788.71 लाख रुपये लागत से निर्मित महत्वाकांक्षी दरबई लघु जलाशय के ग्राम पंचायत भवन केवलारी में आयोजित हुए लोकार्पण कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक श्री दिनेश राय भी शामिल हुए साथ ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन श्री सिद्धार्थ जैन, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग श्री पी.एन.नाग सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। सभी के द्वारा भोपाल से प्रसारित लाईव प्रसारण को देखा व सुना गया। 788.71 लाख रुपये लागत से निर्मित हुई दरबई लघु



जलाशय परियोजना से दरबई ग्राम सहित आस-पास के ग्रामों के कृषकों तथा आमजनों को सीधा लाभ मिलेगा। इस परियोजना तहत 230 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकेगी। जो निश्चित रूप से कृषकों की आय में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगी। विधायक दिनेश राय द्वारा अपने संबोधन में

स्थानीय नागरिकों को दरबई जलाशय कार्य पूर्ण हो जाने पर बधाई दी है। स्थानीय रहवासी भी उनके क्षेत्र में दरबई जलाशय परियोजना के पूर्ण हो जाने पर हर्षित दिखाई दिए तथा वह इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए शासन-प्रशासन धन्यवाद दिए।

मिलाबट खोरो पर जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा

■ छतरपुर। (नव प्रदेश) शहर में मिलावटी तेल के नाम पर लोगों को मौत बेच रहे मिलावटखोरों पर छतरपुर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने की छापामार कार्यवाही, मिलावट खोर सालों से कर रहे थे मिलावटी तेल का व्यापार, बाहर से टैंकरों से तेल मंगा कर गोदामों में डिब्बों में पैकिंग कर बनाते थे हर कंपनी का लोगो लगाकर तेल, जमीन में तेल के कुओ व टैंकरों में भरकर रखते थे तेल, सोमवार की रात करीब 8 बजे नौगांव रोड रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में साहू के तेल गोदाम पर मारा छापा।



भारी मात्रा में अलग-अलग कंपनियों के लोगों व तेल से भरे टैंकर देखकर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने लगाई मिलावटी तेल बेचने वाले गोदाम संचालक को फ्टकार, कहाँ मिलावट खोर समाज के दुश्मन, वही बगल में रखे पीडीएस

के गेहू गोदाम को भी प्रशासन ने किया सील, इसके बाद महोबा बाईपास रोड पर एक गोदाम में भी छापामार कार्यवाही की गई।

जहां पर मालिक के न आने पर गोदाम के ताले तोड़कर प्रशासन ने कार्यवाही की, गोदाम

में आटा की बोरिया व तेल के डिब्बे पाए गए प्रशासन द्वारा उसके सैंपल भरे गए, इसके बाद सटई रोड स्थित एक तेल गोदाम पर भी छापा मार कार्यवाही की गई, कार्यवाही रात करीब 2 बजे तक चलती रही कार्यवाही के दौरान एसडीएम प्रियांशी भंवर, तहसीलदार संजय शर्मा नायाब तहसीलदार अजू लोधी सीएसपी लोकेन्द्र सिंह सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद सिंह डांगी फूड अधिकारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा।

चोरो के हौसले हो रहे बुलंद

छतरपुर। राजनगर थाना अंतर्गत ग्राम लालपुर में टूटे 4-5 घरों के ताले चोरों ने लाखों रुपए नगद के साथ उड़ाए सोने चांदी के जेवर। राजनगर थाना प्रभारी को फोन करके दी गई जानकारी एवं खजुराहो एसडीओपी को भी दी गई सूचना। आपको बता दें कि चोरों ने बिगत 2 महीने पहले भी इसी तरह अज्ञात चोरों ने चार पांच घरों के ताले टोer और साकर काट कर चोरी की थी और दो तीन लाख रुपए नगद एवं 4-5 के सोना चांदी पर हाथ साफ किया था जिसकी रिपोर्ट राजनगर थाने में दर्ज कराई गई थी उन छेरियों का आज तक कुछ पता नहीं चला ना ही चोरों का कोई सुराग लगा। अब देखना होगा की इन चोरियों का भी खुलासा होगा या नहीं या केवल फइल में ही दब कर रह जाएंगी आपको याद दिला दें कि राजनगर थाने में चोरों का दबदबा फिर चढ़कर बोल रहा है लोकल राजनगर मैं भी दर्जनों चोरियों के मामले थाने में दर्ज हैं एवं खजुआ गांव सहित दर्जनों गांवों मैं चोरियों को हुई है उनके मामले दर्ज हैं लेकिन ना तो आरोपी पकड़े जा रहे हैं और ना ही उनका कोई सुराग लग पा रहा है।

युवा मण्डल विकास कार्यक्रम का हुआ आयोजन

■ छतरपुर। (नव प्रदेश) नेहरू युवा केन्द्र छतरपुर युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नेहरू युवा केन्द्र के कोर कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासखंड राजनगर के म.प्र. आदर्ष ग्राम पहाड़ी हीराजू में 11 से 14 दिसम्बर तक चल रहे युवा मण्डल विकास कार्यक्रम में जिला युवा समन्वयक अरविंद सिंह यादव ने गांव के युवाओं को एकत्रित कर एक युवा मण्डल एवं एक महिला मण्डल का गठन किया। इस अवसर पर जिला युवा समन्वयक ने युवाओं को संगठित



होकर आत्मनिर्भर भारत, पिट इंडिया मूमेंट कार्यक्रम, ग्रीन विलेज-क्विलीन विलेज, स्वच्छ भारत अभियान, कारोना जागरूकता अभियान, बीमा

योजनओं एवं अन्य सामाजिक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवा मण्डल के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत से जुड़े एवं

षासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचायें। उन्होंने कहा कि पिट इंडिया कार्यक्रम के तहत पिटनेस का खेल- आधा घंटा रोज के तहत जिलेकूद कार्यक्रम, व्यायाम, योग एवं अन्य पारंपरिक छोटे-छोटे खेल एवं गतिविधियां आयोजित कर पिट इंडिया कार्यक्रम को कामयाब बनायें। कोरोना जागरूकता के अंतर्गत मास्क का उपयोग करे साफ्सफई से रहे एवं उचित दूरी का पालन करे। इस अवसर पर स्वयंसेवक उपस्थित थे।

कृषि कानून के विरोध में किसानों का अर्द्धनग्न रैली प्रदर्शन

■ नरसिंहपुर। (नव प्रदेश) केंद्र द्वारा लागू कृषि कानून के विरोध व दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जिले के किसान संगठनों का प्रदर्शन भी जारी है। सोमवार को एक संगठन ने जहां मंडी में धरना प्रदर्शन देने के बाद रैली निकाली, ज्ञापन दिया। वहीं एक संगठन के सदस्यों ने पचासों किसानों के साथ खैरीनाका से नृसिंह भवन तक अर्द्धनग्न रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। किसानों के प्रदर्शन से नृसिंह भवन परिसर में शाम तक गहमाहगमी का माहौल बना रहा। सोमवार की दोपहर बाद राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के पदाधिकारी-किसानों की भी? वाहनों से खैरीनाका पहुंची। यहां संघ के सदस्यों ने अपने वाहन रोकते हुए दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अर्द्धनग्न होकर रैली शुरू की और नारे लगाते हुए



नृसिंह भवन पहुंच। जहां किसानों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में धरना देकर आंदोलन दौरान शहीद हुए किसानों के लिए दो मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जिस पर कलेक्टर ने जिला स्तर की समस्याओं का निराकरण शीघ्र कराने आश्वासन दिया और

पटेल, नेपाल सिंह, गिरधारी पटेल, कृष्ण कुमार पटेल, जितेंद्र, बंटी सहित बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ रही।मंडी में 5 घंटे धरना प्रदर्शन कर महासंघ ने सौंपा ज्ञापनः राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने कृषि उपज मंडी में सोमवार को केंद्र सरकार के तीन कृषि बिलों को वापिस

लेने व अनाज की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने के लिए गारंटी का कानून बनाने की मांग की। महासंघ ने मंडी परिसर में करीब 5 घंटे तक धरना देते हुए उपवास किया। इस दौरान महासंघ के कई पदाधिकारियों ने अपने विचार रखते हुए कृषि कानून को किसान विरोधी बताया।

किसान विरोधी मानसिकता से हैं ग्रस्त

देश की संसद ने किसानों के व्यापक हित में क्रमशः कृषि व्यापार विपणन, कोटरेट फार्मिंग और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम पारित किए है। जो लोग या संगठन इनका विरोध कर रहे है वे दरअसल किसान विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में राज्यसभा सदस्य केलाश सोनी ने कही। श्री सोनी ने खासतौर से कांग्रेस को आ? हथ लैते हुए आरोप लगाया कि उसके नेता किसान हितैषी कानूनों के संबंध में गलतफहमी पैदा करने करने की असफल कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना रहा कि कृषि सुधार संबंधी केंद्र के ये कानून वास्तव में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। इनके माध्यम से देश के किसानों को सारे बंधनों से मुक्त कर स्वतंत्रता दी गई है ताकि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो सके। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा ये है कि भारत को सारी दुनिया को अन्न खिलाने का हब बनाया जा सके। राज्यसभा सदस्य ने बताया कि केंद्र सरकार ने आश्चर्य किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति जारी रहेगी। सरकार इसके लिए लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने मंडी व्यवस्था भी रखात रखे जाने की बात कही। ये भी कहा कि इनके अलावा जो

लोक अदालत में एक करोड़ आठ लाख के प्रकरणों का निराकरण

सिवनी । (नव प्रदेश) मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण, भोपाल (रिएट) में वीडियो कॉफेससिंग के माध्यम से ऑनलाइन नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत के लिए गठित की गई खण्डपीठ के न्यायमूर्ति श्री सुभाष काकड़े (म.प्र. उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश), सदस्यगण श्री जे. एस. परमार, अधिवक्ता एवं श्री विजय कुमार सहगल, अधिवक्ता के समक्ष कुल 9 प्रकरण प्रस्तुत किए जिनमें से मैसर्स चिनार रिएलिटी प्राइवेट विरूद्ध उमेश खत्री, मैसर्स प्रशांत सागर बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स एवं अन्य विरूद्ध संदीप कुमार सरोड़े, मैसर्स प्रशांत सागर बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स एवं अन्य विरूद्ध सुनील कुमार दुबे, अशुतोष गुप्ता विरूद्ध श्री आदिनाथ डेवलपर्स एवं डी अशोक कुमार एवं अन्य विरूद्ध मैसर्स भोजपाल बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स एवं अन्य कुल 5 प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से किया गया। निराकरण किये गये प्रकरण काफी दिनों से न्यायिक प्रक्रिया



के अन्तर्गत प्रचलन में थे। आपसी सहमति से निराकृत किये गये प्रकरण एक करोड़ आठ लाख छियासी हजार रुपये की लेनदारी से संबंधित थे। प्रकरणों का आपसी निपटरा होने पर पक्षकारगण एवं उनके अभिभाषक गणों ने म.प्र. भू-संपदा अपीलीय अधिकरण (रिएट) की सराहनीय पहल पर प्रसन्नता एवं आभार व्यक्त किया है। भविष्य में भी मध्यस्था कार्यवाही, लोक अदालतों के आयोजन एवं अधिकरण की क्रियाशील सहभागिता को भू-परिसम्पतियों के प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक बताया गया तथा उक्त आयोजन में सक्रिय रूचि दिखाई गई।